Financial Crisis in PSUs.

2859. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are many public sector units which are facing acute financial crisis;

(b) whether it is also fact that some PSUs do not even have the working capital; what are the details of such units; and

(c) if so, the steps taken to assist such public sector units so that they become commercially viable?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) The requirment of funds by the Public Sector Undertakings (PSUs) and the means for meeting the requirement keep varying from time to time and depends upon general conditions in the money market and availability of funds with the PSUs and the Government. Need based financial assistance through plan as well as non-plan budgetary support is provided by the Government to over come resource constraints including working capital requirement subject to the availability of funds.

Action Against Union Leaders for misuse of HBA Bank by Management

2860. SHRI GOVINDRAM M1RI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether union leaders of the Delhi Branches of State Bank of Indore have filed a petition in office of Asstt. Labour Commissioner (C), Kasturba Gandhi Marg, New Delhi against Bank management for taking action against union leaders involved in the misuse of house building advance taken by them; and

(b) if so, what is present position?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM) (a) Yes,
Sir.

(b) Concilidation between the management and union anded in failure and the Conciliation Officer submitted the failure report to the Central Government as required under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947

मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो

2861. श्री राधाकिशन मालवीय: क्या खाद्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के कितने बेस डिपो हैं;

(ख) क्या उक्त बेस डिपुओं की संख्या राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारतीय खाद्य निगम राज्य में और अधिक संख्या में बेस डिपो खोलने का विचार रखता है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली/समपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम ने 61 नामित निगम केन्द्र स्थापित किए हैं जो "बेस डिपो" के नाम से प्रसिद्ध हैं।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता 16 लाख टन (ढकी हुई और कैप दोनों को मिलाकर) से अधिक है। मध्य प्रदेश के लिए खाद्यान्नों के मासिक आवंटन को ध्यान में रखते हुए यह क्षमता "मैक्रो" स्तर पर पर्याप्त समझी गई है।

तथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान निगम मध्य प्रदेश में अतिरिक्त गोदाम का निर्माण कर रहा है। सरकार ने मध्य प्रदेश में कटनी और कापा में दो और नए गोदामों का निर्माण करने संबंधी निगम के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।